भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **5117**

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते

5117. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से उक्त एफटीए के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क में दी गई छूट का एफटीए - वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप दी गई अनुमानित सीमा शुल्क छूट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) वर्ष 2014 से, भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों नामतः मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ओमान के साथ 6 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। यूके और ओमान के साथ एफटीए को समझौते के अनुसार साझेदार देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद क्रियान्वित और लागू किए जाएगें। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता क्रमशः दिनांक 22 दिसंबर 2025 और दिनांक 27 जनवरी 2026 को संपन्न हो चुकी है।

सीमा शुल्क छूट का विवरण व्यापक होने के कारण, इसे पावती बजट दस्तावेजों में https://www.indiabudget.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) जटिल आर्थिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य व्यापार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। एफटीए लागू होने पर विभिन्न क्षेत्रों में शुल्क उन्मूलन, चरणबद्ध कटौती और संवेदनशील/अपवर्जन सूचियों के माध्यम से संतुलित बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।

इन मुक्त व्यापार समझौतों की टैरिफ संरचना और प्रमुख विशेषताओं का विवरण https://www.commerce.gov.in/international-trade/ पर उपलब्ध है।

(ग): भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ किसी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने दिनांक 2 फरवरी, 2026 को एक व्यापार समझौते की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी, 2026 को जारी किया गया। दिनांक 7 फरवरी, 2026 को, अमेरिका द्वारा भारत द्वारा रूस से आयात किए जाने वाले तेल का हवाला देते हुए भारत के कुछ निर्यातों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त यथा मूल्य टैरिफ हटा दिए गए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20 फरवरी, 2026 के उस फैसले के अनुसार, जिसमें पारस्परिक टैरिफ को अमान्य घोषित किया गया था, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया है। सरकार सभी घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में है।

*****

अनुलग्नक

लोकसभा के दिनांक 24 मार्च, 2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2014 से भारत के मुक्त व्यापार समझौते

क्र.स.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी , 2021	1 अप्रैल , 2021
2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी , 2022	1 मई, 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)	2 अप्रैल , 2022	29 दिसंबर, 2022
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)	10 मार्च 2024	01 अक्टूबर, 2025
5	भारत - यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	अनुसमर्थन प्रक्रिया के अधीन है
6	भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)	18 दिसंबर 2025	अनुसमर्थन प्रक्रिया के के अधीन है

*****